

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.316
दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

निजी और सरकारी कंपनियों को खदान ब्लॉक की नीलामी

316 श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा कार्यान्वित खनन सुधारों के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से अब तक देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने खान ब्लॉकों की नीलामी की गई है;
- (ख) वर्ष 2015 से अब तक निजी और सरकारी कंपनियों को आवंटित खान ब्लॉकों का राज्य-वार और कंपनी-वार व्यौरा क्या है;
- (ग) खनन सुधारों के बाद राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी खानें चालू हैं और निजी जांच हेतु अधिसूचित जांच एजेंसियों के नाम क्या हैं; और
- (घ) जिस राज्य में निजी कंपनियों को खानों की नीलामी की गई, वहां राज्य/खान-वार राजस्व की वृद्धि अथवा हानि का व्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से देश में 435 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इनमें से 40 ब्लॉक महाराष्ट्र में नीलाम किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2015 से नीलामी के माध्यम से निजी और सार्वजनिक कंपनियों को आवंटित खनिज ब्लॉकों का राज्यवार व्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट (<https://mines.gov.in/webportal/content/successful-auction-since-2015>) पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2015 से एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17क के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए 24 ब्लॉक आरक्षित किए गए हैं। सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के बाद से नीलाम किए गए 50 खनिज ब्लॉकों का प्रचालन किया गया है। अब तक, देश में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के तहत 25 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है। ये एजेंसियां महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गवेषण कार्य शुरू करने के पात्र हैं। सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

(घ) जिन राज्य सरकारों ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है और उनका प्रचालन किया है, उनके राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि हुई है। नीलामी से पहले और नीलामी के बाद राजस्व संग्रह का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

वर्ष 2015 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिज ब्लॉकों की सूची

क्र. सं.	राज्य	पीएसयू का नाम	क्षेत्र	खनिज
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएमडीसी), राज्य पीएसयू	1327 हेक्टेयर	लौह अयस्क
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएमडीसी), राज्य पीएसयू	25 हेक्टेयर	लौह अयस्क
3	छत्तीसगढ़	एनएमडीसी-सीएमडीसी (एनसीएल) संयुक्त उद्यम सीपीएसयू और हेक्टेयर एसपीएसयू	646.596	लौह अयस्क
4	छत्तीसगढ़	एनएमडीसी-सीएमडीसी (एनसीएल) संयुक्त उद्यम सीपीएसयू और एसपीएसयू	15680 हेक्टेयर	हीरा
5	छत्तीसगढ़	एनएमडीसी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	48.493 हेक्टेयर	अपशिष्ट/गैर-बिक्री योग्य सामग्री के डंपिंग और संबद्ध अवसंरचना की सुविधाओं के लिए गैर-खनिजयुक्त आरक्षित वन भूमि क्षेत्र।
6	गुजरात	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), राज्यहेक्टेयर पीएसयू	80.26.06	चूना पत्थर खनन
7	कर्नाटक	कुद्रेमुख लौह अयस्क लिमिटेड (केआईओसीएल), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	470.4 हेक्टेयर	लौह अयस्क और मैंगनीज
8	कर्नाटक	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	60.70 हेक्टेयर	लौह अयस्क
9	मध्य प्रदेश	मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	383.836 हेक्टेयर	मैंगनीज
10	मध्य प्रदेश	(एमपीएसएमसी), राज्य पीएसयू	21.00 हेक्टेयर	बॉक्साइट

11	ओडिशा	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आईडीसीओएल), राज्य हेक्टेयर पीएसयू	416.512	लौह अयस्क
12	ओडिशा	नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड (नालको), केंद्रीय हेक्टेयर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	697.979	बॉक्साइट
13	ओडिशा	ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), राज्य पीएसयू	456.100	लौह अयस्क
14	ओडिशा	ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), राज्य पीएसयू	365.026	लौह अयस्क
15	ओडिशा	ओडिशा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमईसीएल), राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	24.230	लौह अयस्क
16	ओडिशा	ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), राज्य पीएसयू	168.948	क्रोमाइट
17	राजस्थान	राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (आरएसएमएमएल) राज्य पीएसयू	6189.5	चूना पत्थर
18	राजस्थान	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल), केंद्रीय पीएसयू	400	रॉक फॉस्फेट
19	राजस्थान	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल), केंद्रीय पीएसयू	1100	डोलोमाइट
20	तमिलनाडु	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, केंद्रीय पीएसयू	1144.06.18	समुद्र तट रेत खनिज
21	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (टीएसएमडीसी), राज्य पीएसयू	588.26	चूना पत्थर
22	जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र-पीएसयू	जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र-पीएसयू	77.78	चूना पत्थर
23	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड और (डब्ल्यूबीएमडीएंडटीसी लिमिटेड), राज्य पीएसयू	15.65	चाइना क्ले/फायर क्ले
			13.56	हेक्टेयर

24	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएमडीएंडटीसी लिमिटेड), राज्य पीएसयू	6.47 हेक्टेयर	क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार
----	-----------------	--	---------------	-------------------------

देश में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की सूची नीचे दी गई है:

क्र. सं.	एजेंसी का नाम
1	मैसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2	मैसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
3	मैसर्स कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	मैसर्स एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5	मैसर्स जीएमएमसीओ टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
6	मैसर्स भूशिल्प माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	मैसर्स माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
8	मैसर्स क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर्स
9	मैसर्स पीआरबी इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	मैसर्स रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड
11	मैसर्स जीईएमएस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
12	मैसर्स कुंदन कंसन्ट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	मैसर्स एंजियोटेक कंसल्टेंट
14	मैसर्स नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	मैसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सॉल्यूशंस
17	मैसर्स इकोमेन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
18	मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	मैसर्स वीएम सलगांवकर एंड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड
20	मैसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
21	मैसर्स जियोएक्सपोअर प्राइवेट लिमिटेड
22	मैसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस
24	मैसर्स इंडियन माइन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स
25	मैसर्स नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन-टाटा स्टील लिमिटेड

नीलामी पूर्व और नीलामी पश्चात राजस्व संग्रहण का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	राजस्व (करोड़ रुपये में) वित्त वर्ष 2006-07 से 2014-15	राजस्व (करोड़ रुपये में) वित्त वर्ष 2015-16 से 2023-24
1	ओडिशा	18,194	1,49,423
2	छत्तीसगढ़	7,353	34,648
3	राजस्थान	10,585	27,342
4	कर्नाटक	3,700	22,359
5	मध्य प्रदेश	2,748	5,213
6	आंध्र प्रदेश	3,175*	3,621
7	गुजरात	2,008	3,337
8	गोवा	2,644	1013**
	कुल	50,408	2,46,956

*आंध्र प्रदेश के आंकड़े विभाजन से पहले अविभाजित राज्य के हैं।

**गोवा में खानें कई वर्षों से बंद थीं।